

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4614  
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका राजनयिक संबंध

4614. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका के साथ हमारे राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या नए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों का अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर कोई प्रभाव पड़ा है;
- (ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अमेरिका के साथ व्यापार में कोई परिवर्तन देखा गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहभागिता को दोनों पक्षों का दृढ़ समर्थन प्राप्त है और 20 जनवरी 2025 को नए अमेरिकी प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद से इसमें सकारात्मक गति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में हुई वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने सहयोग के प्रमुख स्तंभों में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए "21वीं सदी के लिए यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों में वृद्धि)" की शुरूआत की। दोनों पक्षों ने 13 फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित द्विपक्षीय साझेदारी के लिए इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) और (ग) अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में अमेरिकी भागीदारी, पारस्परिक शुल्क, अवैध प्रवास, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। आव्रजन से संबंधित आदेश सहित कुछ कार्यकारी आदेशों का अमेरिका में भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग इस मामले से अवगत हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ संपर्क में हैं।

(घ) और (ङ) जहां तक भारत-अमेरिका व्यापार का संबंध है, 12-13 फरवरी 2025 को हुई प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका दोनों ने निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में गहनता लाने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से दोनों नेताओं ने एक नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य - "मिशन 500" निर्धारित किया - जिसका उद्देश्य 2030 तक दोतरफा वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यापार को दोगुना से अधिक करके 500 बिलियन डॉलर करना है। यह स्वीकार करते हुए कि लक्ष्य के इस स्तर तक पहुंचने के लिए नई, निष्पक्ष-व्यापार शर्तों की अपेक्षा होगी, दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर वार्ता की योजना की घोषणा की।

\*\*\*\*\*